



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2015/चैत्र 3, 1937

No. 105]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2015/CHAITRA 3, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015

सं.एल.ए.डी.-एम.आर.ओ./जी.एम./2014-15/25/539.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 में, —
 - विनियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,—

"परिपक्वता (मैच्युरिटी) से पूर्व वापस मंगाने या मोचन (रिडीम) करने का अधिकार

17क. ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यु) लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) ऐसी प्रतिभूतियों को परिपक्वता की तारीख से पूर्व अपने विकल्प (कॉल) पर वापस मंगा सकेगा या परिपक्वता की तारीख से पूर्व मोचन करने का ऐसा अधिकार (पुट) सभी निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को अथवा केवल छोटे (रिटेल) निवेशकों को, उनके विकल्प पर, प्रदान कर सकेगा, निम्नलिखित के अध्यक्षीनः

- परिपक्वता की तारीख से पूर्व ऋण प्रतिभूतियों को वापस मंगाने या उनका मोचन करने के ऐसे अधिकार का प्रयोग निर्गम के निबंधनों के अनुसार किया जाये और प्रस्ताव दस्तावेज में इस संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण किया जाये जिसमें सम्मिलित है वह तारीख जिस तारीख से ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा सकता हो,

प्रयोग की अवधि (जो तीन कार्य-दिवसों से कम नहीं होगी), मोचन की रकम [जिसमें सम्मिलित है प्रीमियम या ब्रूट (डिस्काउन्ट) जिस पर ऐसा मोचन होगा];

- (ख) निर्गमकर्ता या निवेशक उनके द्वारा क्रमशः निर्गमित या धारित सभी ऋण प्रतिभूतियों की बाबत या इस प्रकार निर्गमित या धारित प्रतिभूतियों के भाग की बाबत ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सकेगा;
- (ग) निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम के निबंधनों के अनुसार ऐसे अधिकार के आंशिक प्रयोग के मामले में, ऐसा केवल आनुपातिक आधार पर ही किया जायेगा;
- (घ) ऐसे किसी भी अधिकार का प्रयोग ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से चौबीस महीनों की समाप्ति से पहले नहीं किया जा सकेगा;
- (ङ) निर्गमकर्ता ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के सभी पात्र धारकों को उस तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले सूचना (नोटिस) भेजेगा जिस तारीख से ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा सकता हो;
- (च) निर्गमकर्ता ऐसी सूचना (नोटिस) की एक प्रति उस स्टॉक एक्सचेंज को भी व्यापक प्रसार हेतु प्रदान करेगा जहाँ ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों और व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापन देगा जिसके अंतर्गत ऐसे अधिकार तथा उन धारकों की पात्रता के ब्यौरे दर्शाये जायें जो ऐसा अधिकार पाने के हकदार हों;
- (छ) निर्गमकर्ता निवेशकों को मोचन आगमों (रिडेम्पशन प्रोसीड्स) का भुगतान निवेशकों को देय ब्याज के साथ अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर, जिसके भीतर ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, करेगा;
- (ज) निर्गमकर्ता विलंब की अवधि, यदि कोई हो, हेतु पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करेगा;
- (झ) ऐसे अधिकार का प्रयोग पूर्ण हो जाने के पश्चात्, निर्गमकर्ता सार्वजनिक प्रसार हेतु स्टॉक एक्सचेंज को, प्रयोग अवधि के दौरान जिन ऋण प्रतिभूतियों का मोचन किया गया हो उन ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में और उनके मोचन के ब्यौरों के संबंध में, एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, छोटे निवेशक से उन ऋण प्रतिभूतियों का धारक अभिप्रेत होगा जिनका अंकित मूल्य दो लाख रुपये से अधिक न हो।"

(ii) विनियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

"समेकन और पुनःनिर्गमन

20क. निर्गमकर्ता अपनी ऋण प्रतिभूतियों का समेकन और पुनःनिर्गमन कर सकेगा, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्वधीन:

- (क) उसके अनुच्छेदों, जिनके अधीन उसे निर्गमित किया गया है, में ऐसा सामर्थ्यकारी उपबंध हो;
- (ख) निर्गम निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से हो;
- (ग) निर्गमकर्ता प्रत्येक पुनःनिर्गमन हेतु बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से नया साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) अभिप्राप्त करे और उसे प्रकट किया जाये;
- (घ) ऐसी रेटिंगों को समय-समय पर पुनःविधिमान्य किया जायेगा और यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे प्रकट किया जायेगा;
- (ङ) निबंधन-पत्रक (टर्म शीट) में समेकन और पुनःनिर्गमन के संबंध में समुचित प्रकटीकरण किये जायें।"

(iii) अनुसूची I में, पैरा 3 में, उप-पैरा ख में, खंड (क) में, सारणी में,-

- (क) शब्द "कॉल ऑप्शन", जहाँ कहीं भी दिये हुए हों, शब्द "कॉल" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे;
- (ख) शब्द "पुट ऑप्शन", जहाँ कहीं भी दिये हुए हों, शब्द "पुट" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./348/14/69—जैड बी]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 द्वारा, 6 जून 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 तत्पश्चात्:

(क) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392, द्वारा

(ख) 31 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/43/207, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th March, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

LAD-NRO/GN/2014-15/539.— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2015.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, -
 - (i) after regulation 17, the following regulation shall be inserted, namely,-

"Right to recall or redeem prior to maturity

17A. An issuer making public issue of debt securities may recall such securities prior to maturity date at his option (call) or provide such right of redemption prior to maturity date (put) to all the investors or only to retail investors, at their option, subject to the following:

- (a) Such right to recall or redeem debt securities prior to maturity date is exercised in accordance with the terms of issue and detailed disclosure in this regard is made in the offer document including date from which such right is exercisable, period of exercise (which shall not be less than three working days), redemption amount (including the premium or discount at which such redemption shall take place);
- (b) The issuer or investor may exercise such right with respect to all the debt securities issued or held by them respectively or with respect to a part of the securities so issued or held;
- (c) In case of partial exercise of such right in accordance with the terms of the issue by the issuer, it shall be done on proportionate basis only;
- (d) No such right shall be exercisable before expiry of twenty four months from the date of issue of such debt securities;

- (e) Issuer shall send notice to all the eligible holders of such debt securities at least twenty one days before the date from which such right is exercisable;
- (f) Issuer shall also provide a copy of such notice to the stock exchange where the such debt securities are listed for wider dissemination and shall make an advertisement in the national daily having wide circulation indicating the details of such right and eligibility of the holders who are entitled to avail such right ;
- (g) Issuer shall pay the redemption proceeds to the investors along with the interest due to the investors within fifteen days from the last day within which such right can be exercised;
- (h) Issuer shall pay interest at the rate of fifteen per cent. per annum for the period of delay, if any,
- (i) After the completion of the exercise of such right, the issuer shall submit a detailed report to the stock exchange for public dissemination regarding the debt securities redeemed during the exercise period and details of redemption thereof.

Explanation.- For the purpose of this regulation, retail investor shall mean the holder of debt securities having face value not more than rupees two lakh."

- (ii) after regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely,-

"Consolidation and re-issuance

20A. An issuer may carry out consolidation and re-issuance of its debt securities, subject to the fulfillment of the following conditions:

- (a) there is such an enabling provision in its articles under which it has been incorporated;
- (b) the issue is through private placement;
- (c) the issuer has obtained fresh credit rating for each re-issuance from at least one credit rating agency registered with the Board and is disclosed;
- (d) such ratings shall be revalidated on a periodic basis and the change, if any, shall be disclosed;
- (e) appropriate disclosures are made with regard to consolidation and re-issuance in the Term Sheet."

- (iii) in Schedule I, in paragraph 3, in sub-paragraph B, in clause (a), in the table,-

- (a) the words "call option" wherever appearing shall be substituted with the word "call";
- (b) the words "put option" wherever appearing shall be substituted with the word "put".

U. K. SINHA, CHAIRMAN

[ADVT- III/4/Exty./348/14/69-Z B]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India on 6th June, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/13/127878.

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 were subsequently amended on:

- (a) October 12th, 2012 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392.
- (b) January 31st, 2014 by SEBI (Issue and Listing of Debt Securities)(Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207.